

जीत, न्याय, और एक नॉन-न्यूक्लियर भविष्य: यूक्रेन के खिलाफ रूस की लड़ाई खत्म करने का एक फ्रेमवर्क

सेंटर फॉर ईस्टर्न यूरोपियन डेमोक्रेसी – पोजीशन पेपर नंबर 1.



CEED

JUN 15, 2026



न्याय, जवाबदेही और यूक्रेन तथा विश्व के लिए स्थायी सुरक्षा पर आधारित शांति की एक परिकल्पना ।

“यह लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक रूस खत्म नहीं हो जाता—डीमिलिटराइज्ड, डीन्यूक्लियराइज्ड और अपनी रीजनल/नेशनल पहचान वाले दर्जनों आज़ाद देशों में टूट नहीं जाता ।”

— सेमिल केरिमोग्लू, रूस और ईस्टर्न यूरोप पर लेखक, एनालिस्ट और कमेंटेटर ।

24 फरवरी, 2022 को यूक्रेन पर रूस के बड़े पैमाने पर हमले को चार साल बीत चुके हैं । क्रीमिया पर रूस के पहले कब्जे और 2014 में डोनबास में लड़ाई को बारह साल बीत चुके हैं । लाखों यूक्रेनियन मारे गए हैं या घायल हुए हैं । शहर बर्बाद हो गए हैं । एक आज़ाद देश को सिस्टमैटिक तरीके से खत्म किया गया है । लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है ।

हालांकि, सभी लड़ाइयां खत्म होती हैं । सवाल बस यह है कि कैसे ।

क्या यह लड़ाई इस तरह खत्म होगी जिससे हमले और न्यूक्लियर ब्लैकमेल को इनाम मिलेगा? या यह इस तरह खत्म होगा कि कानून का राज फिर से कायम हो, यूरोप सुरक्षित हो, और ग्लोबल ऑर्डर मजबूत हो?

हमारे सेंटर का नज़रिया साफ है: युद्ध यूक्रेन की निर्णायक मिलिट्री जीत, रूस की लीडरशिप की जवाबदेही, और यूरोपियन और ग्लोबल सिक्योरिटी में स्ट्रक्चरल बदलाव के साथ खत्म होना चाहिए। इसे सेमिल केरिमोग्लू के बताए अनुसार रूस के डीमिलिटराइज़्ड, डीन्यूक्लियराइज़्ड और डिसइंटीग्रेटेड होने के साथ खत्म होना चाहिए। इससे कम कुछ भी यूक्रेन — और दुनिया — को दोहराने के लिए कमज़ोर बना देगा।

I. युद्ध का नेचर

यह कोई इलाके की गलतफहमी नहीं है। यह रूसी साम्राज्यवादी जीत का युद्ध है।

2014 से, रूस ने:

- यूक्रेन के सॉवरेन इलाके पर कब्ज़ा किया।
- यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला किया।
- यूक्रेन में सिस्टमैटिक तरीके से आम लोगों और इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया।
- यूक्रेन में दर्ज युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों में शामिल रहा।
- यूक्रेन के राज्य और पहचान को मिटाने की कोशिश की।

21वीं सदी में ज़ुल्म करते हुए आक्रामक युद्ध छेड़ने को तैयार देश सिर्फ़ एक पड़ोसी के लिए खतरा नहीं है। यह इलाके की स्थिरता और खुद इंटरनेशनल ऑर्डर के लिए एक सिस्टमैटिक खतरा है।

बीसवीं सदी का इतिहास सिखाता है कि विस्तारवादी सरकारें अपनी मर्ज़ी से नहीं रुकतीं। वे तभी रुकती हैं जब उन्हें रोका जाता है।

II. पहली ज़रूरत: हमले की मिलिट्री हार

सिर्फ़ सिक्योरिटी गारंटी काफ़ी नहीं हैं। बिना लागू किए मेमोरेंडम बेकार हैं। 1994 के बुडापेस्ट मेमोरेंडम ने दिखाया कि बिना स्ट्रक्चरल रोकथाम के, पक्के भरोसे फेल हो सकते हैं।

यूक्रेन ने सिक्योरिटी गारंटी के बदले दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा न्यूक्लियर हथियार, जिसमें टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक हथियार शामिल हैं, सरेंडर कर दिया। उन गारंटियों ने हमले को नहीं रोका।

कड़वी सच्चाई यह है:

सिर्फ़ रूस के हमले की साफ़ मिलिट्री हार ही यूक्रेन की आज़ादी को टिकाऊ रूप में सुरक्षित कर सकती है।

इसका मतलब है:

- यूक्रेन की इलाके की एकता की पूरी तरह से बहाली।

- यूक्रेन के सभी कब्जे वाले इलाकों से रूसी सेना की वापसी ।
- रूस की अपनी मर्जी से हमला फिर से शुरू करने की काबिलियत को खत्म करना ।

रुके हुए झगड़े शांति नहीं होते । वे देर से होने वाले युद्ध होते हैं ।

टिकाऊ स्थिरता के लिए साफ़-साफ़ जानकारी चाहिए: हमला पूरी तरह से नाकाम होना चाहिए ।

III. जवाबदेही: एक मॉडर्न नूर्नबर्ग

दूसरे विश्व युद्ध के बाद, दोस्त देशों ने एक ऐसा नियम बनाया जिसने इंटरनेशनल कानून को नया रूप दिया: आक्रामक युद्ध एक जुर्म है ।

नूर्नबर्ग ट्रिब्यूनल ने सिर्फ़ जुर्मों को सज़ा नहीं दी । इसने युद्ध शुरू करने के काम को ही जुर्म बना दिया ।

रूस ने नूर्नबर्ग ट्रायल्स में हिस्सा लेकर उस नियम को पक्का किया । अब वह यह दिखावा नहीं कर सकता कि यह है ही नहीं ।

इसलिए एक सही समझौते में ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए:

- रूस के हमले के जुर्म के लिए एक इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ।
- यूक्रेन पर हमले की प्लानिंग करने और उसे अंजाम देने के लिए ज़िम्मेदार लोगों पर केस ।
- यूक्रेन में दर्ज युद्ध अपराधों और इंसानियत के खिलाफ़ अपराधों के लिए जवाबदेही ।

न्याय बदला नहीं है । यह रोकना है । जवाबदेही के बिना, भविष्य के नेताओं के लिए सबक आसान होगा: अगर आप

राजनीतिक रूप से बचे रहते हैं, तो आप कानूनी नतीजों से बच सकते हैं ।

यह सबक काम नहीं करना चाहिए ।

IV. मुआवज़ा और पुनर्निर्माण

यूक्रेन ने बहुत ज़्यादा तबाही झेली है: टूटा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, तबाह हुए शहर, बेघर हुए परिवार, और खोई हुई पीढ़ियाँ । यूक्रेन के सहयोगियों ने भी युद्ध में यूक्रेन का साथ देने के लिए अरबों डॉलर लगाए हैं । सब कुछ ठीक होना चाहिए ।

यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए काफी हद तक इन चीज़ों से पैसे दिए जाने चाहिए:

- ज़ब्त की गई रूसी सरकारी संपत्ति ।
- मुआवज़े के लिए बनाए गए सिस्टम ।
- युद्ध के बाद के यूरोप पर आधारित इंटरनेशनल पुनर्निर्माण फ़्रेमवर्क ।

यूक्रेन के डिफेंस ने न सिर्फ खुद को बल्कि बड़े यूरोपीय महाद्वीप और उससे आगे की भी रक्षा की है। इन कुर्बानियों को पहचाना जाना चाहिए और उनकी भरपाई भौतिक रूप से की जानी चाहिए, न कि सिर्फ बयानबाज़ी में। इसके अलावा, यूक्रेन का साथ देने वाले सहयोगियों को भी ठीक होना चाहिए।

V. न्यूक्लियर जवाबदेही और नॉन-प्रोलिफरेशन का बने रहना

इस संघर्ष के केंद्र में एक ऐसा मुद्दा है जिसे टाला नहीं जा सकता और जो बुनियादी है। रूस, जिसने दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर हथियारों के जखीरे से सुरक्षित रहते हुए यूक्रेन पर हमला किया, उसे हार के बाद भी उस हथियार को अपने पास रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती।

रूस को अपने न्यूक्लियर हथियार रखने की इजाज़त देना कान के हथियारों का जखीरा ग्लोबल नॉन-प्रोलिफरेशन की क्रेडिबिलिटी को खत्म कर देगा।

यूक्रेन ने रूस की सॉवरेनिटी की गारंटी के आधार पर अच्छी नीयत से अपने न्यूक्लियर हथियार रूस को सौंप दिए थे। फिर रूस ने उसकी गारंटी तोड़ी। अगर रूस एक हमलावर के तौर पर हमला और जुल्म करने के बाद भी अपनी न्यूक्लियर शील्ड बनाए रखता है, तो दुनिया के लिए सबक साफ होगा:

न्यूक्लियर हथियार ही सॉवरेनिटी की असली गारंटी हैं।

वह मिसाल बहुत बड़ी होगी।

यह:

- न्यूक्लियर ब्लैकमेल को पॉलिसी के एक टूल के तौर पर नॉर्मल बना देगा।
- पूरे यूरोप और एशिया में न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को बढ़ावा देगा।
- यूक्रेन पर खुद न्यूक्लियर रीआर्ममेंट पर फिर से सोचने का दबाव डालेगा।
- दशकों से चली आ रही आर्म्स कंट्रोल की कोशिशों को कमज़ोर करेगा।

वह रास्ता नहीं खोला जाना चाहिए।

इसलिए, एक टिकाऊ समझौते के लिए इंटरनेशनल सिक््योरिटी का एक नया नियम बनाना होगा:

अगर आज कोई नया इंटरनेशनल नूर्नबर्ग जैसा ट्रिब्यूनल पाता है कि किसी न्यूक्लियर देश ने दूसरे देश के खिलाफ लगातार हमला किया है और सिस्टमैटिक वॉर क्राइम किए हैं, तो उस हमलावर न्यूक्लियर देश को अपना न्यूक्लियर हथियार छोड़ना होगा। यह एक नया नियम है जिसे इंटरनेशनल कानून में लाना और लागू करना होगा।

जैसे युद्ध के बाद जर्मनी और जापान की हमलावर मिलिट्री क्षमताओं को खत्म कर दिया गया था, वैसे ही युद्ध के बाद रूस को इंटरनेशनल निगरानी में वेरिफाइड और लागू करने लायक न्यूक्लियर हथियार खत्म करने होंगे। उसके न्यूक्लियर हथियार खत्म

करने होंगे। उसके डिलीवरी सिस्टम को बेअसर करना होगा। न्यूक्लियर ज़बरदस्ती करने की उसकी क्षमता को हमेशा के लिए खत्म करना होगा।

यह बदला नहीं है। यह स्ट्रक्चरल रोकथाम है।

यह ग्लोबल सोच में एक लंबे समय से ज़रूरी बदलाव की शुरुआत भी है: न्यूक्लियर हथियार साम्राज्यवादी विस्तार के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर पर काम नहीं कर सकते।

अगर हमलावर न्यूक्लियर देशों को अपने हथियार बिना बदले रखने दिए जाते हैं, तो नॉन-प्रोलिफरेशन खत्म हो जाता है। अगर हमले से हथियार खत्म हो जाते हैं, तो लॉजिक उल्टा हो जाता है। दुनिया — सावधानी से लेकिन सही तरीके से — न्यूक्लियर पर निर्भरता कम करने की ओर बढ़ रही है।

या तो न्यूक्लियर हथियार हमलावरों के लिए ढाल बने रहेंगे, या वे एक बुरे दौर की निशानी बन जाएंगे।

ग्लोबल सिक्योरिटी का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि यह युद्ध क्या सबक सिखाता है।

VI. रूस के रवैये में सुधार

मकसद रूस को एक देश के तौर पर खत्म करना नहीं है। यह रूस के इंपीरियल अटैक के सिद्धांत को खत्म करना है।

सस्टेनेबल शांति के लिए ज़रूरी है:

- यूक्रेन की सॉवरेनिटी को फॉर्मल मान्यता।
- रूस की एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी का त्याग।
- रूस का डेमोक्रेटिक बदलाव।
- होलोडोमोर जैसे स्टालिनिस्ट अत्याचारों सहित ऐतिहासिक अपराधों को मानना।

युद्ध के बाद का जर्मनी दिखाता है कि बड़ा बदलाव मुमकिन है। देश बदल सकते हैं — लेकिन बदलाव हार और सच्चाई से शुरू होता है।

VII. डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को मज़बूत करना

युद्ध ने ग्लोबल गवर्नेंस की कमज़ोरियों को सामने ला दिया है।

ज़रूरी सुधारों में शामिल हैं:

- यूनाइटेड नेशंस को फिर से ज़िंदा करना।
- चल रहे हमले को रोकने वाले वीटो सिस्टम पर फिर से विचार।

- कलेक्टिव सिक्थोरिटी कमिटमेंट को मज़बूत करना ।
- लगातार हमले और युद्ध अपराधों में शामिल देशों को खास इंटरनेशनल भूमिकाओं से साफ़ तौर पर बाहर करना ।

बिना लागू किए कानून का कोई मतलब नहीं है । लागू करने से भरोसा वापस आता है ।

VIII. बड़ा जियोपॉलिटिकल संदर्भ

यूक्रेन में नतीजा दुनिया भर की उम्मीदों को तय करेगा ।

अगर हमला सफल होता है:

- यह दूसरी जगहों पर इसी तरह की कार्रवाइयों की गुंजाइश कम करता है ।
- यह दुनिया भर में विस्तार की चाहत को बढ़ावा देता है ।
- यह यूरोप, एशिया और दूसरी जगहों पर रोकथाम को कमज़ोर करता है ।

अगर हमला पूरी तरह से नाकाम रहता है:

- यह इलाके की आज़ादी को मज़बूत करता है ।
- यह रोकथाम को मज़बूत करता है ।
- यह इलाके में विस्तार की चाहत की कीमत बढ़ाता है ।

दुनिया देख रही है — उन लोगों को भी जो अपने स्ट्रैटेजिक ऑप्शन देख रहे हैं ।

IX. डेमोक्रेटिक ज़िम्मेदारी

एकजुटता की घोषणाएँ काफ़ी नहीं हैं । स्ट्रैटेजी के लिए बयानबाज़ी और रिसोर्स के बीच तालमेल की ज़रूरत होती

है । यूक्रेन का डिफेंस इन पर निर्भर रहा है:

- मिलिट्री सपोर्ट ।
- फाइनेंशियल मदद ।
- इंटेलिजेंस सहयोग ।
- एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ।

मॉडर्न युद्ध ने यह दिखाया है कि स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी – जिसमें सैटेलाइट सिस्टम और कम्युनिकेशन नेटवर्क शामिल हैं – युद्ध के मैदान के नतीजे तय कर सकती हैं । डेमोक्रेसी को यह पक्का करना चाहिए कि जब देश का अस्तित्व दांव पर हो, तो ज़रूरी युद्ध के समय का इंफ्रास्ट्रक्चर डेमोक्रेटिक निगरानी के अलावा सिर्फ़ प्राइवेट हाथों में न रहे ।

वजूद के संघर्ष के समय, देशों के पास स्ट्रेटेजिक एसेट्स की सुरक्षा करने का कानूनी अधिकार होता है। डेमोक्रेटिक जवाबदेही टेक्नोलॉजिकल पावर से मेल खानी चाहिए।

X. युद्ध के बाद का विज़न

अगर यूक्रेन जीतता है, तो नतीजा सिर्फ़ दुश्मनी का ख़त्म होना नहीं होगा।

इसका मतलब होगा:

- एक सॉवरेन यूक्रेन जो यूरोपियन सिक्योरिटी स्ट्रक्चर में इंटीग्रेटेड हो।
- एक नया NATO जो रोकने में सक्षम हो।
- एक यूरोप जो अपनी सिक्योरिटी की रक्षा के लिए तैयार हो।
- एक ग्लोबल रीअफरमेशन कि बॉर्डर को ज़बरदस्ती नहीं बदला जा सकता।
- एक मज़बूत न्यूक्लियर नॉन-प्रोलिफरेशन सिस्टम जो जवाबदेही पर आधारित हो।

न्याय पर बनी शांति बनी रहती है। डर पर बनी शांति ख़त्म हो जाती है।

नतीजा: जीत को समझना

यूक्रेन के लिए जीत का मतलब है:

1. यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता की बहाली।

2. रूस के हमले की मिलिट्री हार।

3. इंटरनेशनल

रूस के लीडरशिप की इंटरनेशनल क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी।

4. नरसंहार, युद्ध अपराधों, अत्याचारों और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए हर्जाने का पेमेंट।

5. यूक्रेन और उसके सहयोगियों के लिए मुआवज़ा और रिकंस्ट्रक्शन।

6. सभी यूक्रेनी बच्चों, युद्धबंदियों और नागरिकों की वापसी।

7. एक हमलावर देश के तौर पर रूस का लागू होने वाला न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट।

8. यूरोपियन और ग्लोबल सिक्योरिटी में स्ट्रक्चरल सुधार, जिसमें रूस की मिलिट्री फोर्स पर लिमिटेशन शामिल हैं।

9. रूस का पिछले इंटरनेशनल शांति समझौतों का पालन करना, जिन पर साइन किए गए थे, लेकिन अब तक उसने उनका सम्मान नहीं किया है ।

यह मैक्सिमलिज़्म नहीं है । यह एक न्यूक्लियर दुनिया में रियलिज़्म है ।

अगर कोई न्यूक्लियर-हथियार वाला देश हमला कर सकता है, तबाही मचा सकता है, अपराध कर सकता है, और स्ट्रक्चरल रूप से बिना बदले रह सकता है, तो इंटरनेशनल ऑर्डर अनसस्टेनेबल हो जाता है ।

अगर अटैक इसके बजाय हार, अकाउंटेबिलिटी और डिस्आर्मामेंट की ओर ले जाता है, तो 21वीं सदी और ज़्यादा स्टेबिलिटी की ओर बढ़ सकती है ।

यूक्रेन की जीत सिर्फ़ एक नेशनल मकसद नहीं है । यह इस बात का टेस्ट है कि कानून पावर को कंट्रोल करता है — या पावर कानून को ओवररूल करती है ।

इतिहास इस पल को हमारे शब्दों से नहीं जज करेगा । यह इसे हमारे कामों और उसके बाद आने वाली शांति के स्ट्रक्चर से जज करेगा ।

और उस शांति को यह पक्का करना चाहिए कि अटैक फेल हो, इंसाफ हो, और न्यूक्लियर फोर्स फिर कभी जीतने के लिए शीलड न बने ।